मुद्दा

बदलाव का अहम दौर

अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

प्रधानमंत्री का लक्ष्य स्पष्ट है। ईज आफ लिविंग और ईज आफ डूइंग बिजनेस पर उनका जोर रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका का महत्व भी वह जानते हैं। मोदी के नेतृत्व में इन आठ वर्षों को भविष्य में उस काल खंड के रूप में जाना जाएगा, जिसमें भारत में आमूलचूल बदलाव हुए।

एकजुट प्रयासों, योजनाओं और उनकी बेहतर निगरानी ने देश के गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव किया है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया और पांच साल में देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.65 करोड़ घर बने, जहां अन्य योजनाओं के जरिये बिजली, पानी, गैस और शौचालय की सुविधा दी गई। 2017 में सौभाग्य योजना शुरू हुई और 18 महीने में ही 2.63 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन पहुंच गया। अगस्त, 2019 में जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ, तब मात्र 17 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंच रहा था। अब यह आंकड़ा 50 प्रतिशत के पार चला गया है। देश में दो अरब के करीब कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। हमने दुनियाभर में टीके निर्यात किए हैं। मार्च, 2020 में महामारी शुरुआत से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

बीते आठ वर्षों में प्रशासन को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। योजनाओं की लीकेज पुरानी बात हो गई है। अब लक्षित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है। इसमें जन धन-आधार-मोबाइल की तिकड़ी का बड़ा योगदान रहा। भारत ने बैंक खाते खोलने के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बना लिया। आधार के जरिये एक अरब से ज्यादा लोगों को बायोमेट्रिक व्यवस्था में जोड़ा गया। वहीं मोबाइल के प्रसार ने वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस तिकड़ी के जरिये 6.5 लाख करोड़ रुपये का लाभ सीधे लोगों के खाते में भेजा जा चुका है। डिजिटल पेमेंट को अद्वितीय विस्तार मिला है। स्थानीय सब्जी वाले से लेकर बड़े-बड़े स्टोर तक, हर जगह यूपीआइ क्यूआर कोड से पेमेंट हो रही है। अप्रैल, 2022 में यूपीआइ के जरिये 9.8 लाख करोड़ रुपये के कुल 5.6 अरब लेनदेन हुए।

महामारी के बाद भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जीएसटी, आइबीसी, रेरा, कारपोरेट टैक्स में कमी, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, श्रम संहिता, वाणिज्यिक कोयला खनन जैसे कई ऐतिहासिक सुधारों के दम पर यह संभव हुआ है। इनके साथ-साथ ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबारी सुगमता) पर ध्यान देने से स्थिति और भी बेहतर हुई है। पांच वर्ष में वर्ल्ड बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम 142 से 63वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। 1,500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं। एफडीआइ के नियमों को भी लगातार निवेशकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 83.6 अरब डालर का रिकार्ड एफडीआइ आया। विभिन्न सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम भी लांच की गई हैं। इनसे देश को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग एवं एक्सपोर्ट हब बनाने में मदद मिलेगी।

दक्षता बढ़ाने और बाधाओं को हटाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया गया है। पीएम गति शक्ति से इसे और विस्तार मिला है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रा परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं और इन पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। आर्थिक सुधारों, कारोबारी माहौल और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का यह अर्थ भी नहीं है कि सामाजिक क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है। बल्कि इस क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसी तरह, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सभी नागरिकों का विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र तैयार करने की दिशा में भी काम हो रहा है। 2020 में नई शिक्षा नीति भी लाई गई है। पोषण और कौशल विकास पर केंद्रित योजनाएं भी शुरू की गई हैं। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के माध्यम से इनोवेशन और उद्यमिता को प्राथमिकता में रखा गया है। भारत में आज 100 से ज्यादा यूनिकार्न हैं और इस मामले में केवल अमेरिका व चीन ही हमसे आगे हैं।

पिछले आठ वर्षों में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सबसे तेजी से विस्तार हुआ है। सीओपी26 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पंचामृत क्लाइमेट एक्शन को सबके सामने रखा और महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं भी जताईं। पीएम ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत का एलान किया और कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात का हब बनेगा। जहां एक तरफ विकसित देश क्लाइमेट फंडिंग को लेकर अपनी जिम्मेदारी से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत ने आगे बढ़कर कमान संभाली है।